अध्याय 3

राष्ट्रीय आय

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं उससे संबंधित अवधारणाएं।
- जीडीपी और जीएनपी के मध्य अंतर।
- राष्ट्रीय आय की गणना साधन की लागत पर तथा बाज़ार कीमत/मूल्य पर।
- राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्य एवं स्थिर मूल्य पर।
- राष्ट्रीय आय के मापन में सावधानियाँ।
- राष्ट्रीय आय से संबंधित अन्य अवधारणाऐ।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र (i) प्राथमिक (ii) द्वितीय (iii) तृतीयक क्षेत्र।

परिचय (Introduction)

राष्ट्रीय आय, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक महत्व का विषय है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था का सम्पूर्ण परिचय होती है। देश की आय उसके उत्पादन क्षमता, उपभोग क्षमता, बचत क्षमता, निवेश व पूंजी निर्माण क्षमता का द्योतक होती है। इसलिए राष्ट्रीय आय का अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।

राष्ट्रीय आय का अर्थ (Meaning of National Income)

1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार—'राष्ट्रीय आय के प्राकलन के लिए किसी अवधि विशेष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को दोहरी बार गिने बिना मापा जाता है।'

राष्ट्रीय आय की गणना (Calculation of National Income)

स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना

- स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कोई वैधानिक संस्था/संगठन नहीं था।
- राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया। उन्होंने राष्ट्रीय आय के आंकलन में कृषि उत्पादन के मौद्रिक मूल्य एवं कुछ गैर कृषि वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना, एक अवैज्ञानिक गणना की संकल्पना बन कर रह गयी।
- राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम वैज्ञानिक प्रयास करने का श्रेय डॉ. वी.के.आर.वी. राव (1931) को जाता है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया। प्रथम भाग में **कृषि क्षेत्र** जिसमें कृषि, वानकी, मत्सयन और शिकार को शामिल किया गया और दूसरे भाग में **कारपोरेट क्षेत्र** जिसमें उद्योग, निर्माण, व्यवसाय, परिवहन व सार्वजनिक सेवाओं को शामिल किया।
- डॉ. राव ने उक्त दोनों क्षेत्रों (कृषि व कारपोरेट) के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद विधि व आय विधि द्वारा की। उत्पाद विधि के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र को तथा आय विधि के अन्तर्गत कारपोरेट क्षेत्र को शामिल किया गया।
- अन्त में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को कृषि व कारपोरेट क्षेत्र से प्राप्त आय में जोड़कर राष्ट्रीय आय के वैज्ञानिक आंकड़े डॉ. वी.के.आर.वी. राव द्वारा प्रस्तुत किये गये।

राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्रित व प्रस्तुत करने का कार्य अन्य लोगों ने भी किया जिनमें प्रमुख है-विलियम डिगबी (1899), फिन्डले शिराज (1911, 1922, 1931), शाह एवं खम्भर (1921) व सी.आर. देसाई (1931-1940), वाडिया एवं जोशी (1913-14)।

स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय आय की गणना

- स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय आय की गणना हेतु भारत सरकार ने वर्ष 1949 में पी.सी. महालिनोबिस की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय आय समिति' का गठन किया। इस समिति में सदस्य के रूप में प्रो. डी.आर. गडगिल व डॉ. वी.के.आर.वी. राव को शामिल किया गया तथा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. साइमन कुजनेट्स समिति के सलाहकार थे।
- राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट वर्ष 1951 में प्रस्तुत की। जिसमें वर्ष 1948-49 की समयावधि की राष्ट्रीय आय 8710 करोड़ रूपये व प्रति व्यक्ति आय 225 रूपये वार्षिक आंकलित की गयी।
- भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) द्वारा किया जाता है जिसकी स्थापना 2 मई 1951 में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सचिवालय में की गयी। यद्यपि इसका प्रारम्भ 1949 में ही एक सांख्यिकीय इकाई के रूप में किया गया था।
- 1948-49 से 1964-65 के राष्ट्रीय आय के अनुमान को 1948-49 के आधार वर्ष (Base Year) पर व्यक्त किया गया। इसे कनवेन्शनल सीरिज कहते है। इसके अन्तर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को 13 उपक्षेत्रों में बांटा गया। इस सीरिज में आय तथा उत्पादन विधि (Income & Production Method) को राष्ट्रीय आय के आकलन में प्रयोग लाया गया।
- आधार वर्ष 1948-49, 1960-61, 1970-71, 1980-81, 1993-94, 2004-2005 तथा वर्तमान में 2011-12 (30 जनवरी-2015 से अपनाया गया) को राष्ट्रीय आय के आंकलन का आधार वर्ष बनाया गया।
- सीएसओ (CSO) का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका औद्योगिक सांख्यिकी विंग (Industrial Statistics Wing) कोलकाता में स्थित है।
- सीएसओ (CSO) अपना वार्षिक प्रकाशन '**राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी**' एनऐएस (NAS) के नाम से जारी करता है।

राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं (Concepts Related to National Income)

राष्ट्रीय आय के मापन हेतु चार अवधारणाएं प्रचलित हैं —

(i) सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product—GDP)
(ii) शुद्ध निवल घरेलू उत्पाद (Net Domestic Product—NDP)
(iii) सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product—GNP)
(iv) शुद्ध निवल राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product—NNP)

सकल घरेलू उत्पाद

अर्थ व उदाहरण | **महत्वपूर्ण तथ्य** | **सूत्र**

सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ—किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उस देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग ही उस देश का 'सकल घरेलू उत्पाद' (जीडीपी) कहलाता है, किन्तु यहाँ यह बता देना उचित होगा कि यह सदैव आवश्वक नहीं कि संपूर्ण जीडीपी देशवासियों की उत्पादक सेवाओं का ही परिणाम हो। वास्तव में जीडीपी का कुछ भाग उन विदेशियों की उत्पाद सेवाओं का भी परिणाम हो सकता है जिन्होंने अपनी पूंजी तथा तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके देश में कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुछ भाग का उत्पादन किया है। अर्थात् जीडीपी में देश में रहने वाले देशवासियों एवं उस देश में निवास करने वाले विदेशियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होती है।

उदाहरण—भारत के संदर्भ में जीडीपी

• भारतीय जो भारत में रहते है के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य	=	8,000 रूपये
• भारत में निवास कर रहें विदेशियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य	=	10,000 रूपये
भारत की जीडीपी का योग	=	**18,000 रूपये**

महत्वपूर्ण तथ्य—जीडीपी के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत् हैं—

- जीडीपी में स्थान महत्वपूर्ण होता है, न कि व्यक्ति।
- जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है।
- जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को दर्शाने में प्रयुक्त किया जाता है।
- इस अवधारणा का प्रयोग तुलनात्मक अर्थशास्त्र में आर्थिक अध्ययनों के लिये किया जाता है।

सूत्र—जीडीपी की अवधारणा को सूत्र के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है—

एक वित्तीय वर्ष में + देश की घरेलु सीमा के भीतर X तथा M के द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन + कुल मौद्रिक मूल्य का योग = जीडीपी

X = भारत में रहने वाले भारतीय।

M = भारत में रहने वाले विदेशी।

देश की घरेलू सीमा का अर्थ

एक देश की जीडीपी ज्ञात करने के लिये उस देश की घरेलू सीमा को जानना अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि जीडीपी के मापन में इस अवधारणा का विशेष महत्व है। साधारण बोलचाल की भाषा में घरेलू सीमा से अभिप्राय उस देश की स्थलीय, सामुद्रिक व राजनीतिक सीमा से लिया जाता है। अर्थात् आर्थिक दृष्टि से देश की घरेलू सीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया जाता है—

- देश की समस्त राजनैतिक व समुद्री सीमा।
- एक या एक से अधिक देशों के बीच चलने वाले वायुयान और जलयान। उदाहरण स्वरूप यदि भारत का वायुयान अमरीका और सिंगापुर जाता है तो यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से भारत की घरेलू सीमा के अन्तर्गत आयेगा जबकि इसके विपरीत अमरीका और सिंगापुर के वायुयान भारत में आते हैं तो यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से अमरीका और सिंगापुर की घरेलू सीमा का क्षेत्र कहलायेगा क्योंकि जब भारत का वायुयान अमरीका और सिंगापुर जाता है तो उस वायुयान सेवा के बदले में प्राप्त राजस्व भारत की जीडीपी में जुड़ता है।
- मछली पकड़ने वाली नौकाएं, तेल व प्राकृतिक गैस के क्षेत्र, यान तथा तैरते प्लेटफार्म जो देश के निवासियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में चलाये जाते हैं और जिसे अंतरराष्ट्रीय समझौते के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त क्षेत्र में तेल खोजने का अधिकार है, ये सभी क्षेत्र देश की घरेलू सीमा के अन्तर्गत आते हैं।
- देश के विदेशों में स्थित दूतावास, वाणिज्य दूतावास व सैनिक प्रतिष्ठान, वैज्ञानिक स्टेशन, सूचना व अप्रवास कार्यालय, सहायता एजेंसियां आदि।

ध्यातव्य हो कि

भारत में स्थित अन्य देशों के दूतावास संबंद्ध देशों की घरेलू सीमा का हिस्सा है।

निवल घरेलू उत्पाद

अर्थ व उदाहरण | महत्वपूर्ण तथ्य | सूत्र

निवल घरेलू उत्पाद का अर्थ—किसी अर्थव्यवस्था की जीडीपी में से एक वर्ष की घिसावट/टूट-फूट (मूल्यह्रास) को घटाकर निवल घरेलू उत्पाद (एनडीपी) प्राप्त किया जाता है। वास्तव में जिन संसाधनों का प्रयोग उत्पादन के दौरान किया जाता है, उनमें उपयोग के दौरान उनका घिसना या टूटना-फूटना होता है, जिसे 'मूल्य ह्रास' कहते हैं। जीडीपी में से इस प्रकार के मूल्य ह्रास के मौद्रिक मूल्य को घटाकर निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है।

उदाहरण—भारत के संदर्भ में एनडीपी

• माना एक वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी	=	18,000 रूपये
• उसी वित्तीय वर्ष मशीनों या उपकरणों में टूट-फूट/घिसावट का मूल्य	=	500 रूपये
भारत की एनडीपी का योग		**17,500 रूपये**

महत्वपूर्ण तथ्य—एनडीपी के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत् हैं—

- यह अवधारणा घरेलू उपयोग में लायी जाती है क्योंकि मूल्य ह्रास की वार्षिक दर अलग-अलग अर्थव्यवस्थाओं में एक ही समय में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए यह तुलनात्मक आर्थिक अध्ययन के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती।
- यह अवधारणा यह ज्ञात करने में सहायक है कि घिसावट के मूल्य का आय पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- अधिक मूल्यह्रास का आय पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अत: मूल्यह्रास को कम करना प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिये चुनौती है। इस चुनौती को पूरा करने के लिये देश में नये अनुसंधान एवं विकास कार्य किये जाते हैं।
- प्रत्येक अर्थव्यवस्था की एनडीपी, उस वर्ष के जीडीपी से हमेशा कम होगी क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है, जो मूल्यह्रास को शून्य कर सके।

सूत्र—एनडीपी की अवधारणा को सूत्र के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है—

जीडीपी – मूल्यह्रास = एनडीपी

सकल राष्ट्रीय उत्पाद

अर्थ व उदाहरण | महत्वपूर्ण तथ्य | सूत्र

सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ—किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग ही उस देश का 'सकल राष्ट्रीय उत्पाद' (जीएनपी) कहलाता है। अत: जीएनपी में देश के नागरिकों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को भी शामिल किया जाता है और देश के भीतर रहने वाले विदेशियों द्वारा अर्जित आय को घटा दिया जाता है।

उदाहरण—भारत के सन्दर्भ में जीएनपी

• भारत में रहने वाले भारतीयों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य।	=	8,000 रूपये
• विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा अर्जित आय है।	=	5,000 रूपये

• भारत में निवासित विदेशियों की आय को घटाया जाता है	=	10,000 रूपये
भारत की जीएनपी का योग		**8000 + 5000 – 10,000 = 3,000 रूपये**

महत्वपूर्ण तथ्य—जीएनपी से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत् हैं—

- जीएनपी किसी अर्थव्यवस्था की बाह्य शक्ति (External Strength) को दर्शाता है।
- जीएनपी यह दर्शाने में मददगार है कि उस देश की वस्तुओं की गुणवत्ता कैसी है?
- जीएनपी में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है न कि स्थान।

सूत्र—जीएनपी की अवधारणा को सूत्र के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है—

देश + वित्तीय वर्ष + जीडीपी + (X – M) + अंतिम वस्तुएँ और सेवाएँ + कुल मौद्रिक मूल्य का योग = जीएनपी

X = निर्यात से प्राप्त आय एवं भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय।

M = आयात मद में किया गया व्यय और भारत में रहने वाले विदेशियों द्वारा अर्जित आय।

निवल/शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद

अर्थ व उदाहरण | **महत्वपूर्ण तथ्य** | **सूत्र**

निवल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ—किसी अर्थव्यवस्था की जीएनपी में से एक वर्ष के मूल्यह्रास को घटाकर 'निवल राष्ट्रीय उत्पाद' (एनएनपी) प्राप्त किया जाता है।

उदाहरण—भारत के सन्दर्भ में एनएनपी

• माना एक वित्तीय वर्ष में भारत की जीएनपी	=	3,000 रूपये
• उसी वित्तीय वर्ष मशीनों या उपकरणों में टूट-फूट का मूल्य	=	500 रूपये
भारत की एनएनपी का योग		**2,500 रूपये**

महत्वपूर्ण तथ्य—एनएनपी के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत् हैं—

- एनएनपी ही देश की राष्ट्रीय आय को दर्शाता है।
- जीएनपी में से प्रति वर्ष होने वाले मूल्य ह्रास (घिसावट) को घटा कर एनएनपी प्राप्त किया जाता है।

सूत्र—एनएनपी की अवधारणा को सूत्र के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है—

जीएनपी – मूल्यह्रास = एनएनपी

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) के मध्य सम्बन्ध

यदि भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों द्वारा अर्जित आय तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा अर्जित आय बराबर है, तो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) में कोई अन्तर नहीं होगा। इसे निम्न रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है—

जीएनपी = जीडीपी, (जब X और M बराबर हो)

बाज़ार कीमत व साधन लागत पर राष्ट्रीय आय

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य दो प्रकार का होता है—

1. साधन लागत
2. बाज़ार कीमत/मूल्य

1. **साधन लागत**—जिन इनपुट का प्रयोग किया जाता है, उन साधनों पर किये जाने वाले व्यय का योग ही उस वस्तु की 'साधन लागत या लागत मूल्य' कहलाता है।

   किसी वस्तु या सेवा उत्पादन में कई तरह के इनपुट जैसे—भूमि, श्रम, पूंजी व उद्यमिता को शामिल किया जाता है और इन आगतों पर किया जाने वाला व्यय क्रमशः लगान, मजदूरी, ब्याज व लाभ का योग ही साधन लागत है। साधन लागत मे सरकार को भुगतान किये गये कर को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शमिल नहीं होता है। परन्तु यदि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कोई सब्सिडी प्राप्त की जाती है तो उसे अवश्य ही साधन लागत में जोड़ा जाता है।

ध्यातव्य हो कि

लागत मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय है।

2. **बाज़ार मूल्य**—किसी वस्तु के बाज़ार मूल्य में उस वस्तु की साधन लागत मूल्य के साथ-साथ अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) जुड़े होते हैं, यही कारण है कि बाज़ार मूल्य, लागत मूल्य की तुलना में अधिक होता है।

   यदि वस्तु मूल-भूत आवश्यकता वाली है, जैसे—खाद्यान्न पदार्थ (गेहूँ, चावल), ईंधन (एलपीजी रसोई गैस, मिट्टी का तेल) या बीज और उर्वरक, के बाज़ार मूल्य अधिक होने पर सरकार सब्सिडी देकर इन वस्तु के मूल्य साधन लागत से भी कम कीमत पर आम जनता को उपलब्ध कराती है और सब्सिडी का बोझ स्वयं वहन करती है। अतः केवल इस स्थिति में ही उक्त वस्तु का बाज़ार मूल्य, लागत मूल्य से कम हो जायेगा।

चालू व स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय

राष्ट्रीय आय की गणना चालू व स्थिर कीमतों पर की जाती है।

चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय—जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो इसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है।

स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय—स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं के उस मौद्रिक मूल्य से है जिसे किसी आधार वर्ष (वर्तमान में 2018-19) के मूल्य पर मापा जाता है। इसे 'वास्तविक राष्ट्रीय आय' कहा जाता है।

ध्यातव्य हो कि

स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय सदैव चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय के सापेक्ष कम ही रहती है क्योंकि चालू कीमतो में मुद्रास्फीति की दर जुड़ी होती है। यदि चालू कीमतों से मुद्रास्फीति की दर घटा दी जाये तो चालू कीमतों में राष्ट्रीय आय व स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय समान ही होगी। अर्थात् चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय व स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय के मध्य का अंतर मुद्रास्फीति के दर के मूल्य के बराबर होगी।

राष्ट्रीय आय की मापन सम्बन्धी सावधानियाँ

राष्ट्रीय आय का मापन करते समय निम्न सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है:

- राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में मापा जाता है।
- अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है।
- उत्पादन प्रक्रिया में सम्मिलित मध्यमवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता।
- राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर की जाती है।

नोट: वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर की जाती है।

- वस्तुए, उपभोग वाली हो या पूंजीगत (मशीन) दोनों ही वस्तुओं के मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किये जाते है।
- राष्ट्रीय आय में विदेशों में रह रहे अपने देश के (भारतीयों) लोगों की आय को शामिल किया जाता है।

राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल न होने वाली मदें

- हस्तान्तरण भुगतान
- पूंजीगत लाभ
- गैर कानूनी गतिविधियों से अर्जित आय
- निषिद्ध वस्तुएँ
- पुरानी वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री
- वित्तीय परिसम्पत्तियाँ
- घरेलू सेवाएँ

- **हस्तान्तरण भुगतान**—ऐसे भुगतान किसी सेवा या उत्पादन के बदले प्राप्त नहीं होते मुख्यत: सामाजिक सुरक्षा हेतु भुगतान किये जाते हैं, हस्तान्तरण भुगतान कहलाते हैं। जैसे-पेंशन, बैंको द्वारा जमा राशि या निक्षेप पर दिया जाने वाला ब्याज, वजीफा, भत्ता आदि।
- **पूंजीगत लाभ**—यह वस्तुओं एवं सेवाओं के वास्तविक उत्पादन के बजाय बजार के स्फीतिकारी प्रभावों के कारण प्राप्त आय है, अत: यह आय भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती।
- **गैर कानूनी गतिविधियों से अर्जित आय**—यह आय एक ओर गैर कानूनी ढंग से अर्जित की जाती है और दूसरी इन आय का मापन कार्य व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है। अत: यह आय भी राष्ट्रीय आय का हिस्सा नही बन पाती।
- **निषिद्ध वस्तुएं**—अफीम आदि के उत्पादन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता।
- **पुरानी वस्तुओं की खरीद व बिक्री**—पुरानी वस्तुओं से तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है, जिनका उत्पादन किसी पूर्व के वित्तीय वर्ष में किया गया है और उस वित्तीय वर्ष में उनका मूल्य उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में जोड़ा जा चुका है। ऐसी पुरानी वस्तुओं के मूल्य को नये वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जायेगा, भले ही उनकी बिक्री नये वित्तीय वर्ष में हो।
- **घरेलू सेवाएं**—एक गृहिणी द्वारा अपने घरेलू कार्य जैसे—कपड़े धोना, खाना बनाना, बरतन साफ करना, अपने बच्चों को पढ़ाना आदि कार्य घरेलू सेवाएं है जिन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता।
- **वित्तीय परिसम्पतियाँ** अंश पत्र, ऋण पत्र आदि का क्रय विक्रय राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाता है क्योंकि ऐसी क्रियाओं से चालू उत्पादन में काई वृद्धि नहीं होती।

राष्ट्रीय आय से संबंधित अन्य अवधारणाएं

- प्रतिव्यक्ति आय (Per Capita Income)
- वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय (Real Per Capita Income)
- हरित राष्ट्रीय आय (Green National Income)
- हरित सूचकांक (Green Index)
- सकल पर्यावरण उत्पाद (Gross Environment Product)
- हरित जीएनपी (Green GNP)

- **प्रति व्यक्ति आय**—एक वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय में से उसी वित्तीय वर्ष की जनसंख्या को भाग देने पर देश की जनसंख्या के हिस्से में जितनी धनराशि आती है, वह उस देश की प्रतिव्यक्ति आय कहलाती है।

ध्यातव्य हो कि

सामान्यत: प्रतिव्यक्ति आय को आर्थिक वृद्धि के मापने के लिए स्वीकार किया जाता है।

$$\text{वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय} = \frac{\text{राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्य पर}}{\text{कुल जनसंख्या}}$$

- **वास्तविक प्रति व्यक्ति आय**—स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय आकलन के पश्चात् जब देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर जो परिणाम मिलता है, उसे ही 'वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय' कहते हैं।
- **हरित राष्ट्रीय आय**—वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध उत्पादन के योग में से उत्पादन की प्रक्रिया में देश के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को जो क्षति पहुंचती है, उसके मौद्रिक मूल्य को घटा दिया जाता है और इस प्रकार हरित राष्ट्रीय आय प्राप्त की जाती है।
  हरित राष्ट्रीय आय = राष्ट्रीय आय—उत्पादन के दौरान पर्यावरण की क्षति का मौद्रिक मूल्य
- **हरित सूचकांक**—विश्व बैंक ने देश की सम्पत्ति के आकलन का एक नया सूचकांक विकसित किया है। इसके अन्तर्गत तीन मानको—1. उत्पादित सम्पत्ति, 2. प्राकृतिक सम्पदा और 3. मानव संसाधन के आधार पर प्रतिव्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। हरित सूचकांक का विकास वर्ष 1995 में हुआ।
- **सकल पर्यावरण उत्पाद**—सकल पर्यावरण उत्पाद का तात्पर्य है-पर्यावरणीय परिणामों के साथ आर्थिक विकास सूचकांक तैयार करना। यह सूचकांक बताता है कि आर्थिक विकास के लिए किसी देश ने अपनी जैव विविधता को कितना नुकसान पहुंचाया अथवा उससे पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ा।
- **हरित जीएनपी**—एक दी हुई समयावधि में प्रतिव्यक्ति उत्पादन की वह अधिक सम्भावी मात्रा है, जो देश की प्राकृतिक सम्पदा को स्थिर बनाए रखते हुए प्राप्त की जा सकती है। वर्ष 1995 में हरित जीएनपी की संकल्पना को प्रारम्भ किया गया था एवं इसमें अभी तक 192 देशों को शामिल किया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र

भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हैं—प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इन क्षेत्रों को भी उपक्षेत्रों में बाँटा जा सकता है, जो निम्नवत्त हैं:

तालिका 3.1: भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और उपक्षेत्र

क्षेत्र	क्षेत्र में शामिल उपक्षेत्र
प्राथमिक क्षेत्र	कृषि एवं पशुपालन + वानिकी +मत्स्यन पालन
द्वितीयक क्षेत्र	खनन व उत्खनन +विनिर्माण + निर्माण + बिजली गैस व जलापूर्ति
तृतीयक क्षेत्र	व्यापार होटल, परिवहन, दूर संचार + वित्त, बीमा, रियल स्टेट, व्यापारिक सेवाएं + सामाजिक व्यक्तिगत व सामुदायिक सेवाएं।

उपरोक्त तालिका से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं, जो कि निम्नवत् हैं:

- प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रकृति द्वारा प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है।
- द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जा सकता है क्योकि इस क्षेत्र में उद्यमी, प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादों का प्रयोग करते हुए एक प्रकार की वस्तु से दूसरी प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करता है जैसे कृषि से प्राप्त कपास को कपड़े में परिवर्तित करना, गन्ने को चीनी में परिवर्तित करना, वनों से प्राप्त लकड़ी को फर्नीचर में परिवर्तित करना।
- तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते है क्योकि इस क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार व वाणिज्यिक सेवाएँ तथा प्रशासनिक सेवाओं आदि को शामिल किया जाता है।
- इन तीनों क्षेत्रों में उत्पादित प्रत्येक वस्तु एवं सेवा का अनुमान लगाया जाता है और इनके अंतर्गत उत्पादित कुल उत्पादों को एक देश का कुल उत्पादन माना जाता है। इन उत्पादों का मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है। इसमें से विदेश में काम कर रहे भारतीय नागरिकों द्वारा भेजी गई आय को भी जोड़ा जाता है।

अध्याय सार संग्रह

- भारत में सांख्यिकी आन्दोलन के जनक पी.सी. महालिनोबिस को कहा जाता है।
- भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा की जाती है।
- भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन वर्ष 1949 में प्रो. पी.सी. महालिनोबिस की अध्यक्षता में किया गया।
- मौद्रिक मूल्य का अर्थ बाजार में प्रचलित वस्तुओं और सेवाओं की चालू कीमत है।
- लागत मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना अप्रत्यक्ष करो को घटा कर की जाती है।
- वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011-12 (30 जनवरी, 2015 से लागू) है।
- पहली मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी (UNDP) द्वारा 1990-91 में जारी की गयी थी
- किसी देश की आर्थिक संवृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदण्ड प्रति व्यक्ति आय (PCI) है।

- पूर्व और वर्तमान में जीडीपी की गणना में अन्तर यह है कि पूर्व में जीडीपी की गणना 'साधन लागत' पर स्थिर मूल्य पर होती थी जिसमें अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता था और सब्सिडी जुड़ी होती थी परन्तु राष्ट्रीय आय की नयी शृंखला (2011-12) आने के बाद जीडीपी 'बाजार मूल्य' पर स्थिर मूल्य पर मापी जायेगी और उसमें अप्रत्यक्ष कर जुड़े होंगे जबकि सब्सिडी घटी होगी।
- भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है।
- भूटान वह देश है, जहाँ 'सकल राष्ट्रीय खुशहाल' सूचकांक, (हैप्पीनैस इंडेक्स) को प्रगति का सूचक माना जाता है।
- नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र से सम्बन्धित हैं।
- हिन्दू सवृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से है।
- राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में (20 रूपये प्रति वर्ष 1867-68) किया गया।
- राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक आधार पर करने का श्रेय वी.के.आर. वी. राव (1925-1929 तथा 1931-1932) को जाता है।
- राष्ट्रीय आय की गणना से सम्बन्धित अन्य लोग विलियम डिग्बी (1899 में), फिन्डले शिराज (1911, 1922, 1931 में), वाडिया एवं जोशी (1913-1914 में), शाह एवं खम्बाटा (1921 में) एवं सी.आर. देसाई (1931-1940 में) हैं।
- दादाभाई नौरोजी की पुस्तक *'पॉवर्टी एण्ड अन-ब्रिटिश रूल इन इण्डिया'* में धन के निष्कासन सिद्धान्त (Drain Theory) का प्रतिपादन किया।
- 'इण्डिया डिवाइडेड' डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की सुप्रसिद्ध कृति है।
- दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन को अनिष्टो का अनिष्ट (सभी बुराइयों की बुराई) संज्ञा प्रदान की थी।
- मानव विकास सूचकांक एचडीआई (HDI) को विकसित करने का श्रेय अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक (पाकिस्तान) और अमर्त्य सेन (भारत) को जाता है।
- एचडीआई (HDI) को मापने का आधार 3 (1. जीवन प्रत्याशा, 2. शिक्षा, 3. प्रति व्यक्ति आय) है।
- एचडीआई (HDI), युएनओ के अंग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी (UNDP) द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है।